बढ़ती बेरोजगारी

भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, पर रोजगार के मोर्चे पर स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिकी की उथल-पुथल और घरेलू बाजार की मुश्किलों के बावजूद देश में निवेश, उत्पादन और उपभोग का स्तर सकारात्मक है. ऐसे में बेरोजगारी में कमी न होना चिंताजनक है. हालिया आंकड़े इंगित करते हैं कि बेरोजगारी दर पिछले 29 महीनों में अपने निचले स्तर पर है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में नौकरीपेशा लोगों की संख्या में लगभग 60 लाख की गिरावट आयी है. उल्लेखनीय है कि नौकरी की चाह रखनेवालों की संख्या में कमी देखी जा रही है, फिर भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है. हमारे देश में रोजगार सृजन मुख्यतः शहरों में केंद्रित रहा है, जो श्रम बाजार में आनेवाले नये लोगों की संख्या का बहुत छोटा हिस्सा है. देश में निजी क्षेत्र की खपत क्षमता कम है और फिलहाल विनिर्माण-क्षेत्र भी सीमित हो रहा है. इस कारण निजी क्षेत्र में नया पूंजी निवेश भी कमतर है. ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए व्यापक सुधारों व प्रयासों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है. देश की 60 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण इलाकों में बसती है और कामकाज की तलाश में शहरों की तरफ रुख करना उनकी मजबूरी होती है. कृषि संकट कई सालों से बरकरार है. ऐसे में गांवों में रोजगार और आमदनी के लिए कदम उठाया जाना चाहिए. आनेवाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकें कार्य क्षेत्रों में आम हो जायेंगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. इन बदलावों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है. हमारे यहां से निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क को लेकर अमेरिका का रवैया और चीन में उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती आमद से हमारे लघु व मध्यम उद्योग जगत पर दबाव बढ़ेगा. स्वाभाविक रूप से ये कारक रोजगार पर नकारात्कामक प्रभाव डालेंगे. भारत में अभी छह से लेकर 16 साल की उम्र के 30 करोड़ बच्चे हैं, जिन्हें निकट भविष्य में काम की जरूरत होगी, जब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे. इस संबंध में ठोस तैयारी के लिए स्कूली स्तर से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए. इसके लिए 'कौशल भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में व्यापक तेजी लानी होगी. रोजगार और उत्पादन में सीधा संबंध है. घरेलू मांग पूरी करने और निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन पर जोर देने की दरकार है. इसके लिए रोजगार और निवेश चाहिए. जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो खपत में भी इजाफा होगा. उम्मीद है कि बैंकों को मजबूत करने, छोटे उद्यमों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने तथा बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की पहलें जल्दी ही बेरोजगारी की बढ़त पर अंकुश लगाने में मददगार होंगी.

रोजगार और उत्पादन में सीधा संबंध है. घरेलू मांग पूरी करने और निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन पर जोर देने की दरकार है. इसके लिए रोजगार और निवेश चाहिए.

अमेरिका की नजर में भारत

पुष्पेश पंत
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gmail.com

अमेरिकी प्रशासन ने यह घोषणा की है कि वह भारत का नाम उस सूची से हटा रहा है, जिसके सदस्यों को उस देश के साथ व्यापार करने में कुछ रियायतें-सहूलियतें दी जाती हैं. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें इससे होनेवाले घाटे की रकम साढ़े पांच अरब डॉलर की धनराशि के आसपास होगी. यह रकम बहुत बड़ी नहीं, परंतु जिस समय यह फैसला किया गया है, वह निश्चय ही अप्रत्याशित तथा क्लेशदायक है. क्योंकि, पुलवामा हमले के बाद भारत यह आशा कर रहा था कि उसका नया सामरिक साझीदार उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के उद्दंड शासकों पर अंकुश लगाने में मददगार होगा.

अमेरिका यानी ट्रंप सरकार का यह आरोप है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों तथा सेवाओं के प्रवेश के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है; उसने इस संबंध में जो भी आश्वासन दिये हैं, उनको पूरा नहीं किया है. यदि इस शिकायत का परीक्षण करें, तो यह बात साफ होते देर नहीं लगेगी कि अमेरिका की शिकायत नाजायज है. भारत के बाजार अमेरिकी आयात से पटे हैं. देश के विकास के लिए जरूरी परिष्कृत तकनीक ही नहीं, विलासितापूर्ण उपभोग की वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध धीरे-धीरे समाप्त हो चुके हैं. बैंकिंग, बीमा, मीडिया आदि में अमेरिकी कंपनियां भारत में सेवाओं के निर्यात के मामले में भी सुविधाएं हासिल कर चुकी हैं. इस दिशा में यदि और अधिक प्रगति नहीं हुई है, तो कारण यह है कि अमेरिका उभयपक्षीय व्यापार को संतुलित करने के लिए एकतरफा रियायतें चाहता है और अपने बाजार को 'सुरक्षित' रखने पर आमादा है.

जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने 'अमेरिका के लिए अमेरिकी उत्पाद' वाला नारा बुलंद किया है. उनकी समझ में चीन तथा भारत ने अमेरिकी कामगारों से रोजगार छीना है और वही अपने सस्ते श्रम और आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिकी में आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार हैं. ट्रंप यह स्वीकार नहीं करते कि उनके देश की कंपनियां तथा उद्यमी अपने लाभ-लागत को ध्यान में रखते हुए चीन या भारत की भूमि से अपना कामकाज करते रहे हैं. मुक्त बाजार का तर्क प्रतिपादित करनेवाला अमेरिका खुद अपने जाल में उलझ रहा है, तो इसका दोष वह भारत के सिर नहीं मढ़ सकता.

चीन के विरुद्ध तो ट्रंप ने बाकायदा वाणिज्य युद्ध (ट्रेड वार) की घोषणा कर दी है. इससे भारत को यह गलतफहमी हुई थी कि इससे होनेवाले घाटे के लिए अमेरिका भारत की तरफ देखने को मजबूर होगा. ईरान के खिलाफ लगाये कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने यह संकेत दिया था कि कम-से-कम कुछ समय के लिए भारत को इनके दायरे से बाहर रखा जायेगा. वह चाबहार बंदरगाह नवनिर्माण की परियोजना में काम जारी रख सकता है, बशर्ते वह ईरान से तेल आयात में कटौती करने को राजी हो जाये. अमेरिका के संधिमित्र सऊदी अरब ने तत्काल भरोसा दिलाया कि वह भारत को तेल संकट से बचायेगा और अधिक मात्रा में तेल सुलभ करायेगा. उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अमेरिका की चाहत पूरी करने का प्रयास किया है. ईरान के साथ अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को संकटग्रस्त करते हुए हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के राजनयिक दिशा-निर्देशों का पालन किया है. इसीलिए हमें यह बात खल रही है कि हमें इस घड़ी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाला जा रहा है.

परमाणु शक्तिसंपन्न उत्तरी कोरिया को अनुशासित करने के लिए अमेरिका को चीन की ही तरफ देखना पड़ेगा. इस नतीजे तक पहुंचने के साथ ही अमेरिका की नजर में भारत का 'अवमूल्यन' होना आरंभ हो जाता है.

असलियत यह है कि ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका है कि चीन अब अमेरिकी प्रतिबंधों से होनेवाले आर्थिक नुकसान को सहने के लिए कमर कस रहा है. उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग-उन का प्रयोग चीन ने एक ताकतवर मोहरे के रूप में बहुत कौशल से किया है. ट्रंप ने कल्पना की थी कि शिखर वार्ता के जरिये वह किम को मोह लेंगे और चीन से अलग कर उत्तर-पूर्वी एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम करने में कामयाब होंगे. यदि ऐसा होता, तो अमेरिका आज चीन पर दबाव बढ़ाने की स्थिति में होता. लग रहा है कि इस मार्चे पर ट्रंप नाकाम रहे हैं, इसलिए तुनकमिजाज परमाणु शक्तिसंपन्न उत्तरी कोरिया को अनुशासित करने के लिए अमेरिका को चीन की ही तरफ देखना पड़ेगा. इस नतीजे तक पहुंचने के साथ ही अमेरिका की नजर में भारत का 'अवमूल्यन' होना आरंभ हो जाता है. अब उस 'सामरिक चतुष्कोण' की बात नहीं सुनी जा रही, जिसके चार प्रस्तावित कर्णधार अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया थे. हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चर्चा भी हाशिये पर पहुंच गयी है.

भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका ने इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं की कि कुछ ही महीनों में भारत में चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की राजनयिक उपलब्धियों की चमक उसके इस फैसले से अचानक घट जायेगी. अमेरिका के ताकतवर राष्ट्रपति के साथ भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंधों की विशेषता का प्रचार जोर-शोर से भारत में किया जाता रहा है. पर्यावरण का संकट हो अथवा अफगानिस्तान में अराजकता-अस्थिरता के निवारण में अमेरिका के उस देश से लौटने के बाद भारत की भूमिका, हम यह मानकर चलते रहे हैं कि हमारे तथा अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में साम्य न सही, कम-से-कम तात्कालिक सन्निपात तो है. ऐसे में, मेरा तो यही मानना है कि इस विषय में पुनर्विचार की जरूरत है.

यह सोचना नादानी है कि अमेरिका- ट्रंप राष्ट्रपति हों या कोई और- चीन तथा पाकिस्तान की तुलना में भारत को अहमियत देगा. 'अमेरिका को अमेरिकियों के लिए' आरक्षित रखने का संकल्प ग्रहण करने के दिखावे से ही ट्रंप चुनाव जीते थे- उसके बाद से अपने आलोचकों को कमजोर करने, उनको विभाजित रखने में ट्रंप अप्रत्याशित रूप से सफल रहे हैं. अब किसी भी अमेरिकी नेता या प्रशासन के लिए अचानक दिशा-परिवर्तन कठिन होगा. भारत को प्राथमिकता देना तो दूर की बात है, दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान को समकक्ष समझनेवाली अमेरिकी नीति में भी कोई अंतर सुदूर भविष्य में आनेवाला नहीं. अमेरिका भलीभांति समझता है कि आज भारत के पास अमेरिका को संतुलित-निरस्त करने के लिए रूसी विकल्प सुलभ नहीं. इसीलिए वह उभयपक्षीय आर्थिक संबंधों तथा दूरदर्शी सामरिक सहमति को अलग करने की बात सोच सकता है. भारत के लिए पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के माहौल में इस जटिल चुनौती का सामना करना आसान नहीं.

स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे शहर

अभिषेक कुमार
टिप्पणीकार
abhi.romi20@gmail.com

स्वच्छता के सिद्धांत को मानें, तो हम पाते हैं कि अगर देश साफ रहेगा तो बीमारियों का प्रसार घटेगा. इससे लोगों के इलाज पर आनेवाला खर्चा बचेगा. इसलिए भारत को सफाई के मामले में विश्व के स्तर पर पहुंचना होगा.

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते हमारे शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इन मूलभूत सुविधाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, देश के हर कोने में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं. लेकिन, इनसे भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छ माहौल, जो तभी मिल सकता है, जब हमारी सरकारें, स्थानीय प्रशासन और हर शहरी की मानसिकता साफ-सफाई को लेकर एकदम स्पष्ट हो. इसके आकलन का एक तरीका स्वच्छता का सर्वेक्षण हो सकता है, जिसकी तमाम कसौटियों पर मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर घोषित किया गया है. देश की सबसे स्वच्छ राजधानियों में भी मध्य प्रदेश को ही अहमियत मिली और भोपाल सबसे साफ राजधानी घोषित की गयी. इस सूची में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी है.

उल्लेखनीय है कि महज 28 दिनों के भीतर 64 लाख लोगों के सीधे फीडबैक से तैयार 'स्वच्छता सर्वेक्षण-2019' रिपोर्ट में देश के जिन 4,237 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें करीब 70 कैटेगरी हैं. यानी किसी शहर का प्रशासन और नागरिक चाह लें, तो देश के 70 शहर किसी न किसी बात में अपनी चमक दिखा सकते हैं. लेकिन हैरानी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के बाहर सफाई के पुरस्कार हासिल करनेवाले शहरों की संख्या कम ही दिखती है. लगता है कि साफ-सफाई को लेकर हमारी सरकारों, प्रशासन और खुद नागरिकों में इसे लेकर कोई उलझन है, जिससे उनके सामने शहरों की स्वच्छता कोई बड़ा एजेंडा नहीं बन पा रही है. वे इसे लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखा पा रहे हैं कि आखिर उनके शहर की इस तरह की पहलकदमियों में कोई हिस्सेदारी क्यों नहीं है और क्या साफ-सफाई का जिम्मा सिर्फ सरकार और प्रशासन के सिर ही होना चाहिए?

दरअसल, भारतीय जनमानस में सफाई को लेकर एक खास किस्म की अड़चन दिखायी देती है. इस बात को ऐसे समझते हैं- हमारे देश में ज्यादातर लोगों का जोर सफाई के बजाय 'पवित्रता' पर रहा है, जो या तो ईश्वर प्रदत्त होती है या आंतरिक उपायों से हासिल की जाती है. अपने परिवेश को साफ-सुथरा रखने के बजाय इसका जोर भीड़ से अलग दिखने पर है. कहीं-न-कहीं हमारे अवचेतन में यह भी बैठा हुआ है कि सफाई हमारा नहीं, किसी और का यानी सरकार का काम है यानी सरकारी वेतन पर रखे गये सफाईकर्मियों का काम है. इसी सोच का नतीजा है कि वर्ण-व्यवस्था ने एक खास वर्ग को यह काम सौंप कर छुट्टी पा ली और बाकी समाज के लिए साफ-सफाई कोई मुद्दा ही नहीं रही. कहने को तो आज वर्ण-व्यवस्था के बंधन कुछ ढीले हुए हैं, लेकिन इस परजीवी मानसिकता से निजात अभी नहीं मिली है कि हमारे सामने पड़ा कचरा उठाना किसी और की जिम्मेदारी है. बल्कि, शहरों में तो ऐसे नजारे आम हैं, जहां तमाम सोसाइटियों के पीछे उस कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जो उन्हीं सोसाइटियों से निकलता है.

देखा जाये, तो अब तक हमारी सरकारें भी इस मामले में ज्यादा लापरवाह रही हैं. वे नगर निगमों को सफाई का पैसा तो देती रहीं, लेकिन इस बारे में कोई प्रेरणा नहीं जगा पायीं कि उन्हें इस पैसे का सही इस्तेमाल भी करना है. हालांकि, मौजूदा केंद्र सरकार ने स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी, दोनों मोर्चों पर सफाई के अभियान शुरू किये. सरकार ने स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत गांवों में हर घर में शौचालय बनाने और खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा, तो स्वच्छ भारत शहरी मिशन में घरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालय और कूड़ा-कचरा प्रबंधन पर भी फोकस किया. पांच साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से आह्वान किया था कि वे देश को साफ-सुथरा बनाने में सरकार की मदद करें. उन्होंने इसके लिए 2019 की डेडलाइन भी सामने रखी थी, क्योंकि यह वर्ष गांधीजी की 150वीं जयंती वर्ष है. उनका मत था कि 2019 तक सारा देश साफ-सुथरा हो जाये, क्योंकि गांधीजी को सफाई बहुत पसंद थी. इसके लिए उन्होंने देश की जनता से यह अपील भी की थी कि देश का हर नागरिक साल में कम-से-कम सौ घंटे सफाई को दे. उन्होंने कहा था कि जिस तरह दिवाली पर हम अपने घर को साफ करते हैं, क्यों न पूरे देश को साफ करने का प्रयास करें.

स्वच्छता के सिद्धांत को मानें, तो हम पाते हैं कि अगर देश साफ रहेगा तो बीमारियों का प्रसार घटेगा. इससे लोगों के इलाज पर आनेवाला खर्चा बचेगा. इसलिए भारत को सफाई के मामले में विश्व के स्तर पर पहुंचना होगा. देश के पचास पर्यटन स्थलों में सफाई की व्यवस्था विश्व स्तर की करनी होगी, तभी भारत के बारे में दुनिया के लोगों की धारणा बदलेगी और हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा.

हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के इरादे सही दिशा में हैं, पर सवाल है कि क्या उनके आह्वानों का असर हमारे शहरवासियों पर पड़ सका है? स्वच्छ सर्वेक्षण की ताजा सूची इस मानसिकता की तस्वीर को काफी हद तक साफ करती है. उम्मीद है कि सफाई को लेकर हमारी सोच को लगे जाले इससे जरूर साफ हो सकेंगे.

बोधि वृक्ष

स्त्री शिक्षा

हमारी एक बुनियादी भूल जो सारी शिक्षा और सभ्यता को खाये जा रही है, वह यह है कि अब तक के जीवन का सारा निर्माण पुरुष के आसपास हुआ है, स्त्री के आसपास नहीं. अब तक की सारी सभ्यता, सारी संस्कृति, सारी शिक्षा पुरुष ने निर्मित की है, पुरुष के ढंग से निर्मित हुई है, स्त्री के ढंग से नहीं. पुरुष के जो गुण हैं, सभ्यता ने उनको ही सब कुछ मान रखा है. पुरुष बिलकुल अधूरा है, स्त्री के बिना तो बहुत अधूरा है. और पुरुष अगर अकेला ही सभ्यता को निर्मित करेगा, तो वह सभ्यता भी अधूरी और खतरनाक होगी. खतरनाक इसलिए होगी, क्योंकि पुरुष के मन में प्रेम बहुत गहराई पर नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा है. जहां महत्वाकांक्षा है, वहां ईर्ष्या होगी, हिंसा होगी, घृणा होगी. पुरुष का सारा चित्त महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है. स्त्री के चित्त में महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि प्रेम है. और हमारी पूरी सभ्यता प्रेम से बिलकुल शून्य है, प्रेम से रिक्त है, प्रेम की उसमें कोई जगह नहीं है. पुरुष ने अपने ही ढंग से पूरी बात निर्मित कर ली है, जिसमें युद्ध प्रमुख है, संघर्ष प्रमुख है, तलवार प्रमुख है. अगर कोई स्त्री तलवार लेकर खड़ी हो जाती है, तो पुरुष उसे बहुत आदर देता है. झांसी की रानी लक्ष्मी को पुरुष बहुत आदर देता है. इसलिए नहीं कि वे बहुत कीमती स्त्रियां थीं, बल्कि इसलिए कि वे पुरुष जैसी स्त्रियां थीं. पुरुष कहता है कि वह मर्दानी थी, इसलिए आदर देता है. लेकिन अगर कोई पुरुष जनाना हो, तो उसका अनादर करता है. पुरुष के मन में हिंसा और महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त किसी बात का कोई सम्मान नहीं है. हजारों वर्षों तक स्त्री को शिक्षा नहीं दी गयी. एक बड़ी भूल थी कि स्त्री अशिक्षित रह जाये. अब कुछ वर्षों से स्त्री को शिक्षा दी जा रही है. और अब दूसरी भूल की जा रही है कि स्त्री को पुरुषों जैसी शिक्षा दी जा रही है. यह अशिक्षित स्त्री से भी खतरनाक स्त्री को पैदा करेगी. अशिक्षित स्त्री कम-से-कम स्त्री थी. शिक्षित स्त्री तो पुरुष के ज्यादा करीब आ जाती है, स्त्री कम रह जाती है. स्त्री शिक्षित होनी चाहिए. लेकिन उस तरह की शिक्षा में नहीं जो पुरुष की है.

आचार्य रजनीश ओशो

आपके पत्र

खत्म हो महिला पुरुष असमानता

आज भले ही महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, पर समाज में उनकी स्थिति से हर कोई वाकिफ है. कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबर न आयी हो चाहे वह छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म का मामला हो या दहेज का. दूसरे देशों से हम अपनी देश की तुलना करें, तो बहुत अंतर देखने को मिलेगा. सरकार कितना भी प्रयास कर ले, जब तक समाज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, महिलाओं को उनका हक पूरी तरह से नहीं मिलेगा. लड़कियों को आज भी पराया समझा जाता है. जन्म के बाद से ही माता-पिता उसे शादी की जिम्मेदारी समझने लगते हैं. पढ़ाई के मामले में भी बेटा-बेटी के बीच असमानता है. समाज के लिए बेटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह अपने आपको हर रूप में ढाल लेती है. महिला और पुरुष दोनों के बीच असमानता खत्म होनी चाहिए. देश की प्रगति के लिए दोनों की भागीदारी बराबर होनी जरूरी है.

श्रीकांत दास, मधुपुर, देवघर

शक और दुख की बात !

राफेल पर बवाल अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि रक्षा मंत्रालय से इसके सौदे की फाइल ही चोरी होने की खबर आयी. अब इस डील पर शक और गहरा हो गया है. बड़ी अजीब बात है कि इतना सब होते हुए भी यह न जाने कैसे हो गया? जब खुद रक्षा मंत्रालय का यह हाल है, तो देश का क्या होगा. बड़े दुख की बात है कि बालाकोट हवाई हमले में मारे गये आतंकियों की संख्या भी विपक्ष जानना चाहता है. इसके साथ ही अब शहीदों के परिवार भी इस संख्या को जानना चाह रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ. इससे भी अधिक दुख की बात है कि पुलवामा हमले में मारे गये अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा ही नहीं मिला है. जबकि सरकार इस चुनावी वर्ष में शहीद के परिजनों के साथ पाने के लिए यह कदम उठा सकती थी, मगर दुर्भाग्य से यह भी नहीं हुआ. इसलिए सरकार को इस पर जल्द कुछ करना चाहिए.

वेद मामूरपुर, नरेला

ओछी मानसिकता से बचें नेता

पुलवामा हमले को कांग्रेस के एक नेता ने दुर्घटना बता कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है. इस बयान की निंदा होने पर, उन्होंने इस घटना को टेरर अटैक माना. ऐसे में उनके पहले वाले बयान को क्या माना जाये? सुर्खियां बटोरने और वोट पाने के लिए कोई यहां तक भी गिर सकता है, यह उस नेता के लिए कोई नयी बात नहीं है. राजनीति में विपक्ष का हमला जायज होता है, पर देश और सेना को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए. नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि देश रहेगा, तभी वे राजनीति करेंगे. वे राजनीति करने विदेश नहीं जायेंगे. कांग्रेस को उस विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर किसी खास तबके को खुश करने और वोटों के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है. नेताओं को भी चाहिए कि वे अपनी मानसिकता बदलें.

सीमा साही, बोकारो

कुछ अलग

महिला जागरूकता का दिवस

शफक महजबीन
टिप्पणीकार
mahjabeenshafaq@gmail.com

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कहते हैं- 'क्योंकि आप महिलाएं हैं, इसलिए लोग आप पर अपनी सोच थोपेंगे. वे आपको बतायेंगे कि कैसे कपड़े पहनें, कैसे व्यवहार करें, किससे मिलें और कहां जायें. लेकिन, मैं कहता हूं कि लोगों के फैसले के साये में आप न रहें, बल्कि अपने ज्ञान की रोशनी में अपनी पसंद-नापंसद तय करें.' एक महानायक की ये लाइनें आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की तमाम लड़कियों-महिलाओं को समर्पित हैं. क्या ही अच्छा हो कि देश के हर पुरुष अमिताभ बच्चन की तरह सोचने लगें.

आज का दिन लड़कियों-महिलाओं के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज महिला दिवस है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है. इसे मनाने का मकसद लड़कियों-महिलाओं के साथ होनेवाले शोषण और भेदभाव को लेकर उठनेवाले विद्रोह के स्वरों को बल देना है. और जागरूकता के जरिये उनका सशक्तिकरण करना है.

न्यूयार्क में 28 फरवरी, 1908 को कपड़ा मिलों में काम करनेवाली लगभग पंद्रह हजार औरतों ने अपने साथ हो रहे शोषण से परेशान होकर एक मार्च निकाला था और नौकरी में कम घंटे देने व बेहतर वेतन की मांग की थी. उसके एक साल बाद यानी 28 फरवरी, 1909 को अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने इस संघर्ष को समर्थन देते हुए उन औरतों को सम्मानित किया और उसे महिला दिवस के रूप में मनाया. क्लारा जेटकिन नामक महिला ने 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के लिए आयोजित एक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मशवरा दिया था. रूस की महिलाओं ने भी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में 'ब्रेड एंड पीस' की मांग की थी. उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर के अनुसार, 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि दुनिया के बाकी देशों में चलनेवाले ग्रेगेरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था. तब से 8 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा. इस वक्त पूरी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर ही चलता है.

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी. उसी साल संयुक्त राष्ट्र ने एक थीम के साथ इसे हर साल मनाने की घोषणा की. वह थीम थी- 'सेलीब्रेटिंग दि पास्ट, प्लानिंग फॉर दि फ्यूचर.' इस थीम से जाहिर है कि महिलाओं के भविष्य के बारे में सोचा जाये. यही वजह है कि दुनियाभर की सरकारें महिलाओं को ढेर सारे अधिकार दे रही हैं, ताकि वे सशक्त हो सकें. इन्हीं अधिकारों में एक है कि कामकाजी महिला को पुरुष के बराबर वेतन दिया जाये. जाहिर है, सामाजिक व राजनीतिक मजबूती के साथ ही आर्थिक रूप से बराबर होना ही महिला सशक्तिकरण है.

इस्लाम में औरतों का मर्तबा बहुत ऊंचा रखा गया है और लड़कियां तो घरों की जीनत मानी गयी हैं. जाहिर है, जिस मजहब में मां के पांवों के नीचे जन्नत की मान्यता हो, वह औरतों को उनके अधिकार से वंचित नहीं रख सकता.

देश दुनिया से

धरती पर अनुमान से कहीं ज्यादा हरियाली

नासा मोडीस सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों पर फरवरी में किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि धरती पर अनुमान से कहीं ज्यादा हरियाली है. हरियाली में हुई इस वृद्धि का कारण चीन और भारत के वनस्पति क्षेत्रों में इजाफा होना है. ये दोनों ही देश इस नये हरित क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं. नेचर सस्टेनबिलिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है इस अतिरिक्त हरियाली के अधिकांश हिस्से के बढ़ने का कारण सक्रिय मानव-नेतृत्व वाला भूमि प्रबंधन है. इस अध्ययन की मानें, तो चीन में अतिरिक्त हरियाली में वनों और कृषि भूमि का क्रमशः 42 प्रतिशत और 32 प्रतिशत योगदान है, लेकिन भारत में 82 प्रतिशत अतिरिक्त हरियाली कृषि भूमि के कारण आयी है, जबकि जंगलों ने केवल चार प्रतिशत का योगदान दिया है. भूमि के क्षरण और उसे बंजर होने से रोकने और वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चीन सक्रिय रूप से वृक्षारोपण कर रहा है. लेकिन विकासशील देशों में उष्णकटिबंधीय जंगलों के लगातार विनाश के कारण होनेवाले नुकसान को कम करने के लिए इतनी हरियाली पर्याप्त नहीं है. न ही कृषि भूमि के तहत ज्यादा क्षेत्र का होना धरती के लिए अच्छा है.

GLOBAL TIMES

कैथलीन नाडे

कार्टून कोना

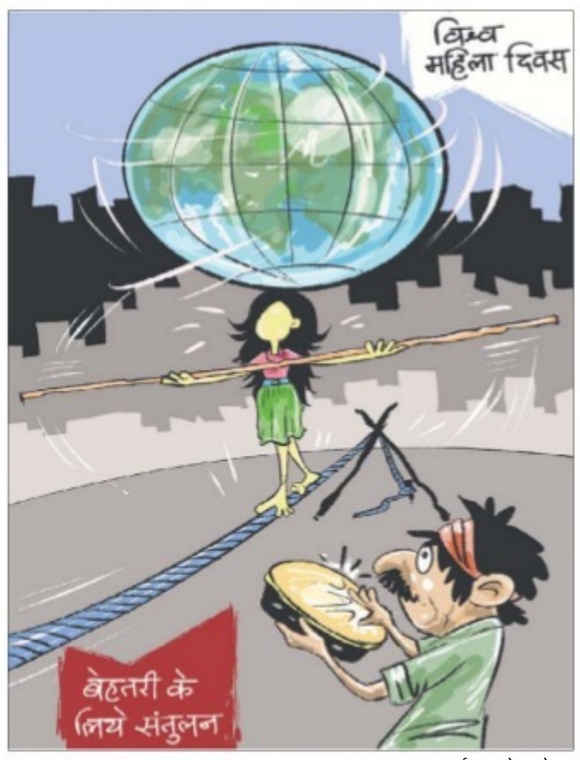

कार्टून : अशोक अदेपाल

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है

क्या रेडियो पाकिस्तान का राहुल को समर्थन कम था, जो अब उनके नेता भी शहीदों का अपमान करना अपना अधिकार समझ बैठे हैं?

स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री

मोदी सरकार द्वारा देश की यह कैसी चौकीदारी? क्या देशहित व देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है? सोचना पड़ेगा.

मायावती, बसपा अध्यक्ष

चुनावी लक

फिर से नरेंद्र मोदी को 'लकी' कुर्सी पर बिठाने की तैयारी

लखनऊ. पांच साल से अधिक समय से कांच के बक्से में रखी एक 'लकड़ी की कुर्सी' जिसे चुनावी माहौल में भाजपा के लिए शुभ माना जाता है, एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि यह कुर्सी पार्टी के लिए काफी भाग्यशाली है, क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे हैं, भाजपा कानपुर के आसपास की सीटें तो जीती ही है, साथ ही केंद्र और प्रदेश में भी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है. पीएम की आठ मार्च की रैली है.

लोकसभा रिव्यू 1984

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा को भंग कर दिया गया और राजीव गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. नवंबर, 1984 के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गयी. चुनाव प्रचार के दौरान राजीव ने लोगों को अपने परिवार के योगदान की याद दिलायी और खुद को एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया. इस चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की.

8वीं लोकसभा-1984

514 लोकसभा सीट	5312 उम्मीदवार मैदान में थे	31 राज्य	
		08 राष्ट्रीय दल	28 छोटे दल
37,95,40,608 मतदाता		63.56% मतदान	

किसको कितनी सीटें मिलीं

पार्टी सीटें | वोट शेयर

404	06	22	10
कांग्रेस	सीपीआइ	सीपीएम	जनता पार्टी
49.10%	2.71%	5.87%	6.89%

72 अन्य 35.43%

चुनाव अपडेट

1 भाजपा ने घोषणापत्र के लिए महिलाओं से सुझाव मांगे

मुंबई. भाजपा की सोशल मीडिया इकाई लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर चुकी महिलाओं से उनके विचार जानने और सुझावों के लिये संपर्क कर रही है. पार्टी ने कहा कि घोषणापत्र को अंतिम रूप देने से पहले समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए यह कवायद की गयी. भाजपा महिला मोर्चा की सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी प्रीति गांधी ने कहा कि पार्टी ने पद्म पुरस्कार विजेता, खेल हस्तियों, चिकित्सकों, रंगमंच कलाकारों, शिक्षाविदों, पर्यवारणविदों, कृषिविशेषज्ञों, सशस्त्र बलों में सेवारत और युद्ध में विधवा हुई महिलाओं से घोषणापत्र को लेकर सुझाव मांगे हैं. गांधी ने कहा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर की महिलाओं तक पहुंचे और इसके बाद उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया.

2 आयोग महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बनायेगा घोषणा पत्र

नयी दिल्ली. सात मार्च (भाषा) दिल्ली महिला आयोग महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर अगले हफ्ते एक घोषणा पत्र तैयार करेगा और इसे अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को भेजेगा. दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने यहां पत्रकारों से कहा कि यह समझने की जरूरत है कि महिलाएं किस हद तक पीड़ित हैं. आगामी चुनाव को देखते हुए आयोग महिला घोषणा पत्र लेकर आयेगा. उन्होंने कहा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से मिलने की कोशिश करूंगी और उनसे इसे अपने एजेंडे में शामिल करने तथा निर्वाचित होने पर इन मुद्दों पर काम करने का अनुरोध करूंगी. मालीवाल ने कहा कि आयोग घोषणा पत्र के लिए विशेषज्ञों से मुलाकात करेगा और अगले हफ्ते तक इसे लेकर आयेगा. आप विधायक पर रेप के आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा, सांसदों-विधायकों से जुड़े ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए.

लोकसभा. महिला आरक्षण का वादा सभी दलों के घोषणा-पत्र में, पर टिकट देने में सभी पीछे

महिलाओं की आबादी 50 फीसदी, संसद व विधानसभा में भागीदारी 15 फीसदी भी नहीं

अनुज कुमार सिन्हा

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है. सामने लोकसभा चुनाव है. चुनाव के दौरान फिर राजनीतिक दल यह वादा करेंगे कि संसद-विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जायेगा. कई साल बीत जाने के बावजूद महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का मामला लटका हुआ है. यह बात सही है कि कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में हैं, लेकिन कई दल ऐसे हैं जिनका इस संबंध में दोहरा चरित्र रहा है और वे महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते रहे हैं. इस पर राजनीति होती रही है. यही कारण है कि देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50 फीसदी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में यह संख्या 15 फीसदी तक भी नहीं पहुंचती. कुछ चुनाव में कुछ राज्यों में इसके अपवाद मिल सकते हैं.

आंकड़ों के बल पर इसे और आसानी से समझा जा सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव के दौरान टिकट बांटने में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है. कम से कम महिलाओं को ही टिकट देकर राजनीतिक दल काम चलाने की कोशिश करते हैं. संसद-विधानसभा तक पहुंचते-पहुंचते यह आंकड़ा और भी कम हो जाता है.

चुनाव में कम टिकट बांटने या कम सांसद-विधायक चुने जाने का मामला कोई नया नहीं है. आजादी के बाद जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए, तो सिर्फ 24 महिला सांसद चुन कर आयीं. दूसरे चुनाव में 23, तीसरे में 37 महिलाएं जीत कर आयीं. 13वें आम चुनाव में पहली बार यह आंकड़ा 50 पार पहुंचा, जब 52 महिला सांसद बनीं. 2014 का चुनाव इस दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहा जब 61 महिला सांसद चुनाव जीत कर संसद में पहुंची. यह रिकॉर्ड है.

प बंगाल सबसे आगे

गत चुनाव यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 14 महिला सांसद पश्चिम बंगाल से बनीं. दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जहां से 13 महिला सांसद बनीं. कई ऐसे राज्य हैं, जहां से एक भी महिला सांसद नहीं हैं. ऐसे राज्यों में झारखंड भी है. सिर्फ 17 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश से ही महिला सांसद हैं. अन्य राज्यों से कोई भी महिला प्रतिनिधित्व नहीं है.

2014 : सबसे ज्यादा महिला सांसद भाजपा से

2014 के आम चुनाव में सबसे ज्यादा 31 महिला सांसद भाजपा से चुनी गयीं. स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या ज्यादा है. कांग्रेस से सिर्फ चार महिला सांसद चुनी गयीं. उसने 60 महिलाओं को टिकट दिया था, मगर 56 महिलाएं चुनाव मैदान में खुद को सिद्ध करने में पिछड़ गयीं.

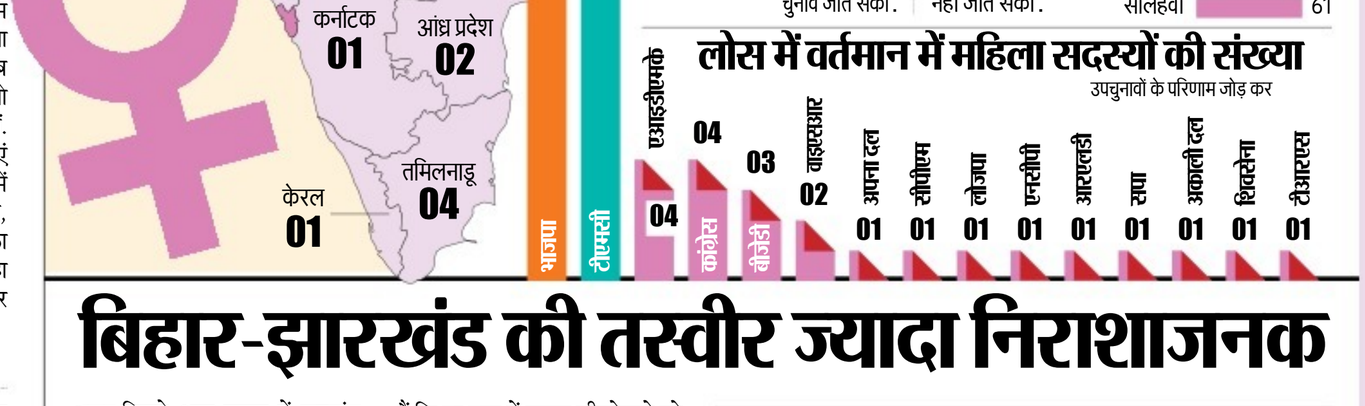

बिहार-झारखंड की तस्वीर ज्यादा निराशाजनक

अगर पिछले आम चुनाव में झारखंड और बिहार में महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ. अव्वल तो पार्टियों ने उन्हें टिकट देने में अन्याय किया, ऊपर से अधिकांश को मतदाताओं ने वोट नहीं दिये. लिहाजा, 10.38 करोड़ की आबादी वाले से सिर्फ तीन महिला सांसद हैं. झारखंड में और खराब हाल रहा. झारखंड की कुल आबादी 3.29 करोड़ में 1.6 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन संसद में झारखंड से एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है.

2014 में ही नहीं, 2009 के चुनाव में भी झारखंड से कोई महिला सांसद नहीं थी. यानी दस साल से झारखंड से कोई महिला सांसद नहीं है. यह असंतुलन बताता है. ऐसी बात नहीं है कि यहां संसद में जानेवाली योग्य महिलाएं नहीं हैं. सच यह है कि राजनीतिक दल टिकट बांटने के दौरान इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर हाल में चुनाव जीतनेवाले को ही टिकट दिया जायेगा. यह देखा जाता है कि उनमें चुनाव जीतने का दम है या नहीं.

इतिहास गवाह है कि इसी बिहार और झारखंड ने महिलाओं को तब संसद में भेजा था, जब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होती थी. झारखंड तो तब बिहार का ही हिस्सा था और पहले चुनाव में ही बिहार ने पटना पूर्वी से तारकेश्वरी सिन्हा (कांग्रेस) और भागलपुर सुषमा सेन को संसद में भेजा था. उसके बाद भी बिहार से कई महिला सांसद बन चुकी हैं जिन्होंने मंत्री तक का पद संभाला है. अब समय आ गया कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हों, ताकि कोई भी, किसी दल से भी जीते, जीतेंगी महिलाएं ही.

रीता वर्मा
धनबाद से लगातार चार बार सांसद रहीं और केंद्र में मंत्री भी बनीं.

झारखंड की महिला एमपी मंत्री भी बनीं

दूसरे आम चुनाव (1957) में हजारीबाग से ललिता राज लक्ष्मी (राजमाता) और चतरा से विजया राजे चुनाव जीती थीं. दोनों रामगढ़ राज परिवार से थीं और छोटानागपुर-संताल परगना जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर संसद में पहुंची थीं. राजमाता 1962 का चुनाव औरंगाबाद (बिहार) से और 1967 का चुनाव धनबाद से जीती थीं. विजया राजे ने तो चतरा से ही 1962 और 1967 का चुनाव जीता था. रामगढ़ राजा के परिवार से शशांक मंजरी भी थी, जिन्होंने 1962 का चुनाव पलामू से जीता. यानी 1967 तक झारखंड क्षेत्र से जो भी महिलाएं संसद गयीं, उनमें रामगढ़ राजपरिवार से जुड़े लोग ही थे. इसके बाद कई अन्य महिलाएं भी चुनाव जीतीं. इनमें कमला कुमारी (पलामू), रीता वर्मा (धनबाद), आभा महतो (जमशेदपुर), सुमति उरांव (लोहरदगा) शामिल हैं. सुशीला केरकट्टा, सुमन महतो को भी संसद में जाने का मौका मिला. रीता वर्मा धनबाद से 1991 से 1999 तक लगातार चार बार सांसद रहीं. कमला कुमारी पलामू से तीन बार सांसद रहीं. रीता वर्मा व सुमति उरांव मंत्री भी रहीं.

झारखंड की अब तक की महिला सांसद

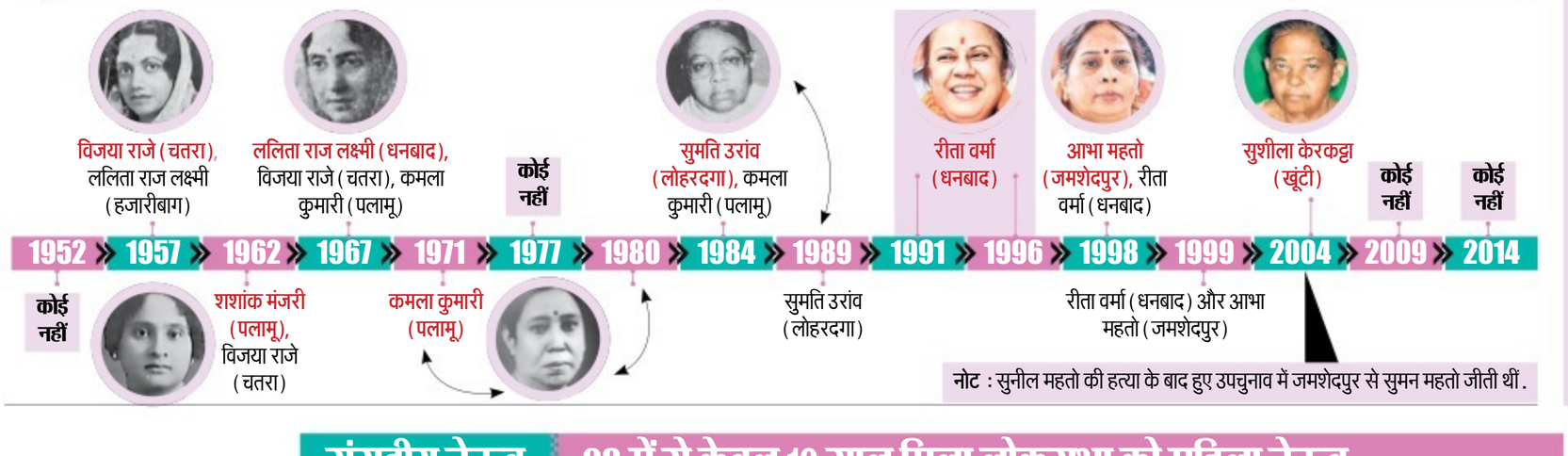

बिहार की महिला सांसद
1952-2014

1952 सुषमा सेन (भागलपुर), तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व)

1957 सत्यभामा देवी (नवादा), शकुंतला देवी (बांका), तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़)

1962 सत्यभामा देवी (जहानाबाद), शकुंतला देवी (बांका), रामदुलारी सिन्हा (पटना), तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़)

1967 तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़)

1971 कोई नहीं (झारखंड क्षेत्र को हटा दिया गया है)

1977 कोई नहीं

1980 कृष्णा शाही (बेगूसराय), माधुरी सिंह (पूर्णिया), किशोरी सिन्हा (वैशाली), रामदुलारी सिन्हा (शिवहर)

1984 मनोरमा सिंह (बांका), चंद्रभानु देवी (बलिया), प्रभावती देवी (मोतिहारी), कृष्णा शाही (बेगूसराय), माधुरी सिंह (पूर्णिया), किशोरी सिन्हा (वैशाली), रामदुलारी सिन्हा (शिवहर)

1989 उषा सिन्हा (वैशाली)

1991 लवली आनंद (वैशाली), गिरिजा देवी (महाराजगंज), कृष्णा शाही (बेगूसराय)

1996 भागवती देवी (गया), कांति सिंह (विक्रमगंज)

1998 रमा देवी (मोतिहारी), मालती देवी (नवादा)

1999 कांति सिंह (विक्रमगंज), रेणु कुमारी सिंह (खगड़िया), श्यामा सिंह (औरंगाबाद)

2004 मीरा कुमार (सासाराम), रंजीत रंजन (सहरसा) कांति सिंह (आरा), मीना सिंह (विक्रमगंज)

2009 मीना सिंह (आरा), मीरा कुमार (सासाराम), पुतुल कुमारी (बांका), अश्वमेघ देवी (उजियारपुर), रमा देवी (शिवहर)

2014 वीणा देवी (मुंगेर), रमा देवी (शिवहर), रंजीत रंजन (सुपौल)

नोट : बिहार की महिला सांसदों में से जो झारखंड निर्माण के पहले इस क्षेत्र से चुनी गयी थीं, अलग राज्य बनने के बाद उनके नाम बिहार की सांसद सूची से हटा दिये गये.

कार्टून कोना बीबीसी

बलों के अभियान का न हो चुनावी इस्तेमाल : पूर्व एडमिरल

नयी दिल्ली. पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास (सेवानिवृत्त) ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि उसे राजनीतिक दलों को पुलवामा हमला, बालाकोट की हवाई कार्रवाई और विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान से वापस आने के मुद्दे को मतदाता को लुभाने के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे एक खुले खत में रामदास ने पार्टियों द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए सशस्त्र बलों के शौर्य का इस्तेमाल किये जाने पर चिंता व्यक्त की.

संसदीय नेतृत्व 68 में से केवल 10 साल मिला लोकसभा को महिला नेतृत्व

अब तक हुई हैं केवल दो महिला लोकसभा अध्यक्ष

आरके नीरद

भारतीय संसद के 68 साल के इतिहास में अब तक केवल दो बार महिला लोकसभा अध्यक्ष हुईं. पहली बार यूपीए सरकार के समय 2009 में मीरा कुमार और दूसरी बार एनडीए सरकार के समय 2014 में सुमित्रा महाजन को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया. सुमित्रा महाजन वर्तमान समय में भी लोकसभा अध्यक्ष हैं. इनसे पूर्व 14 बार (1952 से 2004 तक) लोकसभा के चुनाव हुए और इतनी ही बार लोकसभा के गठन के साथ इसके अध्यक्ष चुने गये. 1952 में जीवी मावलंकर से 2004 में सोमनाथ चटर्जी तक हर बार पुरुष सांसद को ही लोकसभा की अध्यक्षता का अवसर मिला. तब भी, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री (1967, 1971 और 1080) थीं, लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी, जीएस ढिल्लो और बलराम जाखड़ ही हुए. मीरा कुमार कांग्रेस का दलित चेहरा थीं. वह पहले राजनयिक थीं. फिर राजनेता बनीं. उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था. करीब 19 साल बाद उन्हें कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर पेश किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनीं. 2014 के चुनाव में कांग्रेस की विदाई हो गयी और भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार बनी. इसने सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष के तौर पर पेश किया और लोकसभा ने इसे स्वीकार कर लिया.

मीरा कुमार

मीरा कुमार के पिता बाबू जगजीवन राम प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे. मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गयी थीं और स्पेन, ब्रिटेन और मॉरीशस में उच्चायुक्त रहने के बाद वह राजनीति में आ गयीं. 1985 में वह पहली बार बिजनौर से संसद में चुन गयीं. 1996 और 1998 में भी वह सांसद चुनी गयीं. 2004 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बिहार के सासाराम से जीता था. तब उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया था.

सुमित्रा महाजन

सुमित्रा महाजन इंदौर से भाजपा सांसद हैं. वह इंदौर से 1989 से 2014 तक लगातार आठ बार सांसद निर्वाचित हुई हैं. वह आठ बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला सांसद हैं. इंदौर में वह 'सुमित्रा ताई' यानी सुमित्रा दीदी के नाम से लोकप्रिय हैं. 1989 में पहली बार सांसद बनने से पहले वह इंदौर विधानसभा चुनाव लगातार तीन बार हार चुकी थीं. सांसद बनने के बाद पहली बार 2002 से 2004 तक वह केंद्र सरकार में मंत्री रहीं.

तीन महिला उपसभापतियों ने 26 साल किया उच्च सदन का संचालन

राज्यसभा के अब तक 12 उपसभापति हुए हैं. इनमें तीन महिला रहीं. राज्यसभा ने 1962 में अपना उपसभापति वायलेट अल्वा को चुनाव. वह 1969 तक इस पद पर रहीं. उसके बाद भारतीय संसद के उच्च सदन में महिला उपसभापति चुने जाने का अवसर डॉ नजमा ए हेपतुल्ला को मिला. वह पहली बार 1988 में इस पद पर चुनी गयीं. करीब एक वर्ष तक इस पद पर रहीं. तीसरी महिला उपसभापति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनीं और 1986 से 1988 तक इस पद पर रहीं. उनके बाद हेपतुल्ला को दोबारा 1988 में यह अवसर मिला व लगातार 16 सालों तक उन्होंने उच्च सदन का बतौर उपसभापति संचालन किया.